बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 212 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 09 जून 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

कथित 912 करोड़ बैंकिंग घोटाले की जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आज एक जनहित याचिका दायर की गई। इसमें एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नोएडा स्थित एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से जुड़े कथित बैंकिंग घोटाले की न्यायालय की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह एक न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति का गठन करे। इस समिति में भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों को शामिल किया जाए। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों की मदद से बड़े पैमाने पर कॉरपोरेट और बैंकिंग धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है।

जब तक कांग्रेस इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेगी तब तक उसका कोई भविष्य नहीं- आप

नई दिल्ली।

वपक्षी इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक सोमवार (8 जून) को दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में हुई. इस बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी समेत 20 से अधिक दलों के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया. इस बैठक में आम आदमी पार्टी और डीएमके ने हिस्सा नहीं लिया. इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि एक मिशन के लिए इंडिया गठबंधन बना था. जैसे बीजेपी ने एनडीए बनाया वैसे ही दूसरी तरफ हमने इंडिया गठबंधन बनाया. उन्होंने कहा कि गठबंधन का एक धर्म होता है और धर्म यह है कि जो अंदर वही बाहर होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेगी तब तक उसका कोई भविष्य नहीं है.

आप बीजेपी के साथ दिख रहे हैं- सोमनाथ भारती

सोमनाथ भारती ने कहा, आपने एक तरफ कहा हम गठबंधन के रूप में लड़ेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे, लेकिन अंदरखाने आप बीजेपी के साथ दिख रहे हैं. उन्होंने बताया कि दिल्ली में लोकसभा का चुनाव हुआ. जिसमें 4/3 के फॉर्मूले पर फैसले हुआ. तीन सीटों पर कांग्रेस को मिलीं. जिन पर अरविंद केजरीवाल ने खुलकर प्रचार और समर्थन किया और वोट मांगे. उन्होंने आगे कहा कि जो चार सीटें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को मिलीं, उन पर राहुल गांधी को छोड़ दीजिए कांग्रेस का कोई भी नेता हमारे समर्थन में जनता से वोट मांगने नहीं उतरा तो काहे का गठबंधन है यहां तक की उन्होंने हमें हराने का प्रयत्न भी किया. इसके बाद जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ. उसमें खुलकर बात सामने आ गई. जब कांग्रेस शून्य सीट लाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुशी जाहिर करती है कि आम आदमी पार्टी हार गई.

सोमनाथ भारती ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला

सोमनाथ भारती ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, ठकेजरीवाल का हारना इस तरह संभव हुआ कि वोट काट दिए गए, वोट चुरा लिए गए. 1 लाख 48 हजार वोट मेरे समय में थे और 9 महीने बाद यह संख्या घटकर 1 लाख 2 हजार रह गई. अब राहुल गांधी ने इस वोट चोरी की चर्चा क्यों नहीं की.

जब वे वोट चोरी की चर्चा करते हैं तो दिल्ली को छोड़ देते हैं. इसलिए मैं कहता हूं कि गठबंधन धर्म को निभाना कांग्रेस को नहीं आता है.

दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश- जज को मर्डरर कहने वाले वीडियो-पोस्ट तुरंत हटाओ, चलेगा अवमानना का मुकदमा

नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक सुनवाई में उन सभी वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है, जिनमें एक वरिष्ठ हाईकोर्ट जज को साकेत में इमारत ढहने की घटना का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें मर्डरर कहा गया था। कोर्ट की अवकाश खंडपीठ ने (न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और न्यायमूर्ति मधु जैन) ने कहा कि ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट न केवल न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि जनता के न्याय व्यवस्था में विश्वास को भी कमजोर करते हैं। बेंच ने संकेत दिया कि वह संबंधित खातों को ब्लॉक करने के आदेश पर भी विचार कर सकती है। सुनवाई के दौरान बेंच ने टिप्पणी की कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऐसे कंटेंट के खिलाफ सक्रिय रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा सोशल मीडिया इतना शक्तिशाली कैसे हो गया क्या हम इन प्लेटफॉर्म्स पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते जब उन्हें इतना अमर्यादित कंटेंट पता चल जाए तो उन्हें खुद ही उसे हटाना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि वीडियो में दिए गए बयान सचाई पर आधारित नहीं हैं, बल्कि अदालत को बदनाम करने और स्कैंडलाइज करने का प्रयास हैं। बेंच ने आशा जताई कि जनता ऐसे बयानों पर कोई ध्यान न दे। 30 मई को साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत के ढहने से छह लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. कपिल ककड़ ने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स (पूर्व ट्विटर) और लिंक्डइन पर कई वीडियो जारी किए। इन वीडियो में ककड़ ने आरोप लगाया कि एक हाईकोर्ट जज ने अवैध निर्माण रोकने वाली याचिका खारिज कर दी थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) ने इस पर आपराधिक अवमानना की याचिका दायर की। बार एसोसिएशन का कहना है कि ककड़ के आरोप पूरी तरह गलत और भ्रामक हैं। वास्तव में जज का आदेश केवल याचिका वापस लेने की अनुमति देने वाला था, क्योंकि उसमें संपत्ति मालिक को पक्षकार नहीं बनाया गया था।

22 मौतें और दर्जनों खामियां, फिर भी कई सरकारी विभाग बेदाग; क्या करता है निगरानी तंत्र

नई दिल्ली । मालवीय नगर अग्निकांड में 22 लोगों की मौत के बाद होटल मालिक और रसोइये की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन लाइसेंस जारी करने, भवन नियमों का पालन सुनिश्चित करने, फायर एनओसी की निगरानी करने और समय-समय पर निरीक्षण की जिम्मेदारी निभाने वाले सरकारी विभाग अब भी कार्रवाई के दायरे से बाहर हैं। सवाल यह है कि जब अवैध निर्माण, क्षमता से अधिक कमरे और सुरक्षा संबंधी कमियां वर्षों से मौजूद थीं, तो संबंधित विभाग क्या कर रहे थे। उपहार, अनाज मंडी, मुंडका, विवेक विहार, सैदुलाजाब और अब मालवीय नगर... राजधानी में हर बड़े हादसे के बाद यही सवाल उठता है, लेकिन जवाबदेही अक्सर निजी संचालकों तक सिमट कर रह जाती है और निगरानी तंत्र फिर बेदाग बच निकलता है। पुलिस ने मामले में होटल मालिक लवकेश बजाज और एक रसोइए को गिरफ्तार किया है। दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इसके बावजूद घटना के पांच दिन बाद भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि लाइसेंस देने, संचालन की निगरानी करने और सुरक्षा मानकों की जांच करने वाले विभागों में किस स्तर पर चूक हुई। सरकार की ओर से जारी ताजा निरीक्षण रिपोर्टें यह दिखाती हैं कि राजधानी के कई इलाकों में बड़ी संख्या में होटल और गेस्ट हाउस बिना पर्याप्त अग्नि सुरक्षा इंतजामों के संचालित हो रहे थे। सात जून को जारी राजस्व विभाग की रिपोर्ट में विभिन्न जिलों में 130 से अधिक परिसरों का निरीक्षण किया गया, जिनमें अनेक जगहों पर फायर एनओसी, भवन स्वीकृति, सार्वजनिक लाइसेंस और सुरक्षा उपकरणों से जुड़ी गंभीर कमियां पाई गईं। कई प्रतिष्ठानों को नोटिस दिए गए, कुछ को सील किया गया और कुछ के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली, दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पूर्व, मध्य और पश्चिमी जिलों में होटलों और गेस्ट हाउसों में फायर एनओसी की नहीं मिली है। कई मामलों में अधिकारियों ने पाया कि लाइसेंस में स्वीकृत कमरों की संख्या से अधिक कमरे संचालित करने के अलावा यहां कई खामियां हैं। यही खामियां प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े कर रही हैं। पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि किसी भी व्यावसायिक आवासीय प्रतिष्ठान के संचालन में कई एजेंसियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती हैं। इनमें स्थानीय निकाय, अग्निशमन विभाग, पुलिस, राजस्व प्रशासन और अन्य लाइसेंसिंग एजेंसियां शामिल हो सकती हैं। ऐसे में केवल होटल संचालक की भूमिका की जांच पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। जांच का विषय है कि जिन विभागों की जिम्मेदारी निगरानी और नियमों का पालन सुनिश्चित करने की थी, उन्होंने अपना काम ठीक से किया था या नहीं।

दिल्ली में पानी संकट पर कांग्रेस का हल्ला बोल, मटका फोड़ प्रदर्शन से बीजेपी सरकार को घेरा

नई दिल्ली । दिल्ली में बढ़ती पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली कांग्रेस ने बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में प्रदेश भर के ब्लॉक में मटका फोड़ प्रदर्शन आयोजित किए गए. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दिल्ली जल बोर्ड और बीजेपी सरकार जल संकट से निपटने में पूरी तरह विफल साबित हो रही हैं, जिसके कारण आम लोगों, खासकर गरीब तबके को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने खुद बुराड़ी समेत कई इलाकों में आयोजित मटका फोड़ प्रदर्शनों में हिस्सा लिया. करावल नगर जिले के बुराड़ी स्थित दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय के बाहर हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी शामिल हुए. प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और पानी की समस्या का तत्काल समाधान करने की मांग उठाई गई.

गरीब विरोधी नीतियों का लगाया आरोप

देवेंद्र यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रेखा गुप्ता सरकार गरीबों के हितों की अनदेखी कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों को राजधानी से बाहर करने की सोची-समझी रणनीति के तहत उनके घर तोड़े जा रहे हैं. भीषण गर्मी में उन्हें पीने के पानी के लिए तरसाया जा रहा है, बिजली कटौती और गंदगी जैसी समस्याओं से जूझने के लिए मजबूर किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियां गरीबों के अस्तित्व पर संकट पैदा कर रही हैं.

कांग्रेस शासनकाल की उपलब्धियां भी गिनाईं

देवेंद्र यादव ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के दौरान गरीबों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए इन-सीटू फ्लैट योजना शुरू की थी और अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया था. उनके अनुसार, कांग्रेस के 15 वर्षों के शासनकाल में दिल्लीवासियों को पानी की ऐसी गंभीर समस्या का सामना नहीं करना पड़ा था.

आप और बीजेपी दोनों पर साधा निशाना

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए फ्लैटों को गरीबों को आवंटित करने के बजाय पिछली आम आदमी पार्टी सरकार और वर्तमान बीजेपी सरकार ने उनकी उपेक्षा की. उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों सरकारों ने गरीबों की मजबूरियों पर राजनीति की और उनके पुनर्वास के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया.

जल संकट के खिलाफ सड़क पर उतरेगी कांग्रेस

देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता पानी की कमी के मुद्दे पर लगातार संघर्ष करेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे. उन्होंने मांग की कि जिन इलाकों में गरीब आबादी रहती है, वहां तुरंत पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि कई क्षेत्रों में जानबूझकर दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइनों से पानी नहीं पहुंचाया जा रहा है.

ट्रिपल इंजन सरकार पर भी उठाए सवाल

देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली की बीजेपी सरकार पड़ोसी बीजेपी शासित राज्यों से राजधानी की जरूरतों के अनुसार अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने में नाकाम रही है.

उन्होंने दावा किया कि तथाकथित ट्रिपल इंजन सरकार होने के बावजूद दिल्ली के लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जो सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है. प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष मगेश त्यागी, नरेंद्र सोनी, नारायण दत्त, प्रदीप राणा, श्याम सिसौदिया, राजन पांडे, खेम चंद सैनी, विनय त्यागी, अनिल बंसीवाल, अमित डेडा, विनोद कुमार और मुकेश पाल सहित कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

भर्ती एजेंसियों ने मनमाना रवैया अपनाया- तेलंगाना पुलिस भर्ती केस पर सुप्रीम टिप्पणी, अभ्यर्थी को मिली राहत

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तेलंगाना में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के एक अभ्यर्थी की उम्मीदवारी बहाल करने का फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि राय की भर्ती एजेंसियों ने एक ऐसे आपराधिक मामले के आधार पर नियुक्ति से इनकार कर मनमाना रवैया अपनाया, जो एक असफल प्रेम संबंध से जुड़ा था और बाद में लोक अदालत में समझौते के जरिए समाप्त हो गया था। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में गजुल थिरुपति नाम के युवक ने याचिका दायर की थी। इसे मंजूरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तेलंगाना हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के उस फैसले को भी रद्द कर दिया, जिसमें स्टाइपेंडरी कैडेट ट्रेनिंग पुलिस कांस्टेबल (एससीटीपीसी) पद के लिए उनके अस्थायी चयन को रद्द किए जाने को सही ठहराया गया था। अपने फैसले में न्यायमूर्ति मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि नियोक्ता किसी आपराधिक मामले में बरी या मुक्त हो चुके उम्मीदवार की उपयुक्तता का आकलन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा निर्णय मनमाना नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राय और उसके अधिकारी मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकते। इसलिए, जब ऐसे फैसले की न्यायिक समीक्षा की जाती है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह मनमाना न हो, तो यह दिखाया जाना चाहिए कि (क) रिकॉर्ड पर ऐसा सामग्री मौजूद हो जिससे यह संकेत मिले कि वास्तव में नैतिक अधमता वाला अपराध किया गया था और (ख) उम्मीदवार के खिलाफ ऐसा ठोस सामग्री हो, भले ही वह बरी या मुक्त हो गया हो। जस्टिस मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, यह कहना कि समझौते का मतलब अपराध स्वीकार करना है, बिना किसी आधार के है। इसके अलावा, यह कहना कि अपीलकर्ता ने समझौता इसलिए किया क्योंकि वह दोषी था, पूरी तरह से गलत और तर्कहीन है। अदालत ने यह भी दर्ज किया कि याचिकाकर्ता ने आपराधिक मामले की पूरी और सही जानकारी दी थी। इसके साथ ही, तथ्यों को छिपाने का कोई आरोप नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती अधिकारियों की इस दलील पर आपत्ति जताई कि लोक अदालत में हुआ समझौता अपराध स्वीकार करने के समान है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला दो वयस्कों के बीच संबंध से जुड़ा था और अधिकारियों को सिर्फ इसी आधार पर किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हर प्रेम संबंध विवाह तक नहीं पहुंचता और सिर्फ इसलिए कि संबंध विवाह में नहीं बदला, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि एक पक्ष ने दूसरे के साथ धोखाधड़ी की। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की खंडपीठ का फैसला रद्द कर दिया और सिंगल जज के उस आदेश को बहाल कर दिया, जिसमें अपीलकर्ता की नियुक्ति पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया था। अपीलकर्ता ने अपने आवेदन में बताया था कि उस पर पहले आईपीसी की धारा 417, 420 और 506 (धारा 34 के साथ) के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह मामला एक महिला ने दर्ज कराया था, जिसने आरोप लगाया था कि उसने उससे शादी करने का वादा किया था लेकिन बाद में किसी और महिला से शादी कर ली।

रचा इतिहास

प्रतिभा किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती, आवश्यकता होती है तो केवल सही अवसर, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन की। उत्तर प्रदेश सरकार इसी सोच को साकार कर रहे है समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संचालित इन आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने इस वर्ष जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड और बोर्ड परीक्षाओं में उल्लेखनीय सफलता हासिल कर यह साबित कर दिया है कि यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उचित वातावरण उपलब्ध कराया जाए तो ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। प्रदेश में इस वर्ष सर्वोदय विद्यालयों के 11 विद्यार्थियों ने जेईई मेंस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, जबकि छात्रा प्रीति ने जेईई एडवांस्ड के लिए क्वालीफाई कर विद्यालयों की उपलब्धियों में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। विद्यार्थियों की इस सफलता पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सभी छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा को सामाजिक और आर्थिक बदलाव का सबसे प्रभावी माध्यम बनाया है। इसी दृष्टिकोण के तहत समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इन विद्यालयों का उद्देश्य केवल औपचारिक शिक्षा प्रदान करना नहीं, बल्कि ऐसे विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए तैयार करना भी है, जिनके पास संसाधनों की कमी के कारण बड़े अवसरों तक पहुंच नहीं बन पाती। आज ये विद्यालय हजारों विद्यार्थियों के लिए उम्मीद का केंद्र बन चुके हैं। यहां विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आवास, भोजन, पुस्तकें, वर्दी तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जैसी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। मिर्जापुर के मड़िहान स्थित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय को विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विकसित किया गया है। डॉ. अरुण कुमार तिवारी, ट्रस्टी एक्सप नॉलेजेन फाउंडेशन तथा टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के सीएसआर सहयोग से यहां जेईई और नीट की निःशुल्क तैयारी के लिए 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की स्थापना की गई है। इस केंद्र का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को वही सुविधाएं उपलब्ध कराना है जो सामान्यतः बड़े शहरों के महंगे कोचिंग संस्थानों में मिलती हैं। विशेषज्ञ शिक्षकों का मार्गदर्शन, नियमित टेस्ट, आधुनिक अध्ययन सामग्री और प्रतियोगी वातावरण ने विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसका परिणाम इस वर्ष सामने आया, जब यहां से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने देश की सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की। इस वर्ष सर्वोदय विद्यालयों के कुल 11 विद्यार्थियों ने जेईई मेंस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर विभाग और प्रदेश का नाम रोशन किया है। मिर्जापुर के मड़िहान स्थित सर्वोदय विद्यालय की छात्राएं दामिनी पटेल, अंजना वर्मा, सृष्टि, शिवानी और रागनी ने जेईई मेंस परीक्षा में सफलता हासिल की। इन छात्राओं ने यह साबित किया है कि ग्रामीण परिवेश में रहकर भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जा सकता है। इन्हीं छात्राओं में शामिल प्रीति ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए जेईई एडवांस्ड के लिए भी क्वालीफाई किया है। यह उपलब्धि विशेष महत्व रखती है क्योंकि जेईई एडवांस्ड को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिना जाता है और इसके माध्यम से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में प्रवेश मिलता है। इसके अलावा देवरिया के मेहौना सर्वोदय विद्यालय के विकास यादव और अंकित सिंह, बाराबंकी के तेरावां सर्वोदय विद्यालय के अभिषेक मिश्रा, बस्ती के जोगियाटप्पा भानपुर सर्वोदय विद्यालय के अमित कुमार तथा मिर्जापुर के परसिया सर्वोदय विद्यालय के ऋषिकेश भारती ने भी जेईई मेंस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। सफलता की इस कहानी में प्रीति और दामिनी पटेल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दोनों छात्राओं को आईआईटी मद्रास के प्रतिष्ठित बीबीए और एमबीए कार्यक्रमों के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि सर्वोदय विद्यालयों में उपलब्ध कराए जा रहे गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक वातावरण का प्रमाण भी है। सीमित संसाधनों वाले परिवारों से आने वाली इन छात्राओं ने अपने परिश्रम और दृढ़ संकल्प से यह सिद्ध कर दिया है कि अवसर मिलने पर कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। आज उनकी सफलता प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 103 आवासीय जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इन विद्यालयों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां विद्यार्थियों को केवल पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा तक सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं, व्यक्तित्व विकास, खेलकूद और अन्य रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से सर्वांगीण विकास का अवसर दिया जाता है। सरकार की यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधारों पर विशेष ध्यान दिया है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक विभिन्न स्तरों पर बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल शिक्षण सामग्री, विज्ञान प्रयोगशालाओं का विकास, पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण तथा तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही छात्रवृत्ति योजनाओं, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों, यूनिफॉर्म वितरण और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष कार्यक्रमों ने विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाया है। सर्वोदय विद्यालयों की सफलता इन प्रयासों की सार्थकता को भी सिद्ध करती है। कभी जिन परिवारों के लिए उच्च शिक्षा केवल एक सपना हुआ करती थी, आज उनके बच्चे आईआईटी, मेडिकल कॉलेजों और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं। यह बदलाव केवल शैक्षिक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का भी संकेत है।

कब बुझेगी युद्ध की आग

मानव इतिहास में सबसे पीड़ादायक अध्याय है युद्ध। यह एक ऐसा भयानक तांडव है जो मानवीय सपनों को पलभर में राख कर देता है। युद्धों ने हमेशा विनाश की नई श्रृंखला को ही जन्म दिया। विजय की होड़ में मानवता दांव पर लगा दी गई है। हालांकि विजेता भी अंततः खोखली जीत के साथ रह जाता है। शहर तो उजड़ते ही हैं। महंगाई आसमान को छूती है। गरीबी दोगुणा हो जाती है। पश्चिम एशिया के युद्ध से पूरी दुनिया परेशान है। युद्ध ने हमेशा इस सत्य को उजागर किया है कि अंधकार में शांति के व्यावहारिक उपाय खोजे जाने चाहिए। कूटनीति को प्राथमिकता देते हुए बातचीत होनी चाहिए लेकिन न अमेरिका मान रहा है, न ईरान और न ही इजराइल। युद्ध विराम और समझौते की बातचीत के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प शांति-समझौते की बात तो करते हैं लेकिन युद्ध जारी रखे हुए हैं। ईरान के आईआरजीसी ने कुवैत और बहरीन के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर हमले कर तबाही मचा दी है क्योंकि इन हवाई अड्डों पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। कुवैत हवाई अड्डे पर हमले में भारत के उज्जैन निवासी श्रमिक की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हुए। अमेरिका ने ईरान के राडार और मिसाइल ठिकानों पर हमले किए और ईरान के ड्रोन मार गिराने का दावा किया। कुवैत, बहरीन और अन्य खाड़ी देशों में युद्ध के सायरन बज उठे हैं। लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनाई देती है। ऐसे में अनुमान लगाना कठिन नहीं कि युद्ध की ज्वाला कभी भी भड़क सकती है। ईरान और अमेरिका में शांति समझौते में सबसे बड़ी बाधा इजराइल बना हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रम्प की कुछ सुनने को तैयार नहीं। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। इजराइल ने हाल ही के वर्षों में अपने सभी युद्ध विराम समझौतों का लगातार उल्लंघन किया है। युद्ध विराम समझौतों के बावजूद वह गाजा पर बमबारी जारी रखे हुए है। ईरान अपनी अरबों रुपए की सम्पत्तियां रिलीज करने की मांग पर अड़ा हुआ है। जबकि ट्रम्प संवर्धित यूरेनियम हासिल करने की जिद पकड़े हुए हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य मार्ग खुलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। अब तो छोटा सा देश ओमान भी अमेरिका को धमकाने में लगा हुआ है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान रोका जाए और प्रस्ताव में यह निर्देश भी है कि यदि भविष्य में युद्ध की कार्रवाई अपरिहार्य हो तो पहले कांग्रेस (संसद) की मंजूरी ली जाए। प्रस्ताव के पक्ष में 215 और उसके खिलाफ 208 वोट आए। राष्ट्रपति ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी के 4 सांसदों ने भी क्रॉस वोटिंग की और डेमोक्रेट्स का समर्थन किया। इससे पहले सीनेट में भी ट्रम्प-समर्थक सांसदों ने उनके खिलाफ वोट दिए थे। संसद में पारित प्रस्ताव के जरिए राष्ट्रपति की निरंकुश युद्ध-शक्तियों को भी सीमित किया गया है। यह घटनाक्रम और परिदृश्य राष्ट्रपति ट्रम्प के लिए राजनीतिक और संसदीय आघात से कम नहीं है। फिर भी राष्ट्रपति ट्रम्प पारित प्रस्ताव को 'असंवैधानिक' करार देते हुए 'वीटो' कर सकते हैं, लेकिन वह राष्ट्रपति और संसद के बीच टकराव की नौबत से बचना चाहेंगे। यदि अमरीकी संसद राष्ट्रपति की 'वीटो' को बेअसर करना चाहेगी तो 290 सांसदों को प्रस्ताव के पक्ष में वोट करना होगा। वह 'महाभियोग' सरीखी स्थिति ही होगी, लिहाजा हमें असंभव लगती है। एक नई रिपोर्ट ने सबको चौंका कर रख दिया है कि इजराइल अमेरिका की जासूसी कर रहा है। ईरान से शांति वार्ता में जुटे अमेरिकी अधिकारियों पर पैनी निगाह रखे हुए है ताकि वह समझौते के किसी भी प्रयास को विफल बना सके। वैसे तो युद्ध से पूरा विश्व प्रभावित है लेकिन भारत भी इससे अछूता नहीं है। खाड़ी देशों में करीब एक करोड़ भारतीय रहते हैं। उनके जीवन की रक्षा भी भारत के लिए चिंता का विषय है। होर्मुज स्ट्रेट में अभी भी बड़ी संख्या में जहाज फंसे हुए हैं। उनके क्रू मेम्बर्स भी अधिकतर भारतीय हैं। देश में ऊर्जा संकट गम्भीर हो रहा है। तेल भंडार पर्याप्त रखने के लिए भारत विकल्प तलाश रहा है। एलपीजी और सीएनजी गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। महंगाई की मार आम जनता को झेलनी पड़ रही है। रुपए की कीमत गिर रही है जिससे आयात बिल बढ़ रहा है। ऊर्जा सुरक्षा, विदेशी मुद्रा भंडार और घरेलू भंडार सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय निवेशक शेयर बाजार से अपना धन निकाल रहे हैं। किसानों के लिए फर्टिलाइजर की कमी दिखाई देने लगी है। यद्यपि भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार तमाम चुनौतियों के बावजूद बहुत अच्छी बनी हुई है लेकिन आरबीआई ने अपनी तिमाही मौद्रिक नीति में विकास दर का अनुमान घटा दिया है और महंगाई बढ़ने का अनुमान जताया है। अन्तर्राष्ट्रीय रेटिंग एजैंसी मूडीस ने भविष्यवाणी की है कि अगर कुछ दिनों में युद्ध न रोका गया तो अमेरिका में भी आर्थिक मंदी फैल सकती है। अमेरिका में मुद्रास्फीति की दर 4.2 फीसदी तक बढ़ चुकी है, जो अमेरिका में अप्रत्याशित है। दुनियाभर के देशों की अर्थव्यवस्था दबाव में है। अगर आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ तो परिणाम भयंकर होंगे। बेहतर यही होगा कि ट्रम्प शर्तों पर न अड़कर कुछ ऐसा मार्ग निकालें जिससे ईरान भी सहमत हो और होर्मुज मार्ग भी खुल जाए। युद्ध विराम बहुत नाजुक स्थिति में है, इसलिए ट्रम्प को इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को लगाम भी कसनी होगी, ताकि प्रस्तावित समझौते पर आगे बढ़ सकें।

सम्पादकीय...

नकल मुक्त शिक्षा कैसे हो?

हाल ही में रद्द हुई नीट परीक्षाओं के विवाद से देशभर में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ये परीक्षाएं दोबारा करवाने की बात भी हो रही है लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि भारत में होने वाली परीक्षाओं में या तो पेपर लीक किए जाते हैं या फिर परीक्षाओं के समय बड़े स्तर पर नकल की जाती है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता रहती है कि जो परीक्षाएं हों, न तो उनके पेपर लीक हों, न ही ऐसी परीक्षाओं में नकल हो लेकिन असल में वास्तविकता इसके विपरीत हो हो जाती है। ऐसा नहीं है कि देश में नकलमुक्त शिक्षा सम्भव नहीं है। कमी है तो सिर्फ इसके प्रबंधन की। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश का हर युवा, देश के विकास में योगदान करे। इसके लिए उन्होंने 'कौशल विकास' का विशेष मंत्रालय भी बनाया है। सर्वविदित है कि सरकार हर नौजवान को नौकरी नहीं दे सकती है। निजी क्षेत्र, कृषि या स्वरोजगार ही वो रास्ते हैं, जिनके जरिये एक नौजवान अपने जीवन में स्थायित्व ला सकता है। जीवन जीने की चुनौतियां अनेक हैं। जिनका सामना करने के लिए हर युवा का संतुलित विकास होना आवश्यक है। व्यक्तित्व विकास का एक महत्वपूर्ण अंग शिक्षा है। अशिक्षित युवा के लिए चुनौतियां और भी बढ़ जाती हैं, पर समस्या इस बात की है कि जिन्हें शिक्षित या डिग्रीधारी माना जाता है, वे स्वयं ही अंधेरे कुएं में पड़े हैं। डिग्रियां हाथ में हैं, फिर भी वे शिक्षित नहीं कहे जाते। वैसे तो संपूर्ण भारत में प्राथमिक, माध्यमिक और स्नातक स्तर की शिक्षा व्यवस्था अपनी आत्मा और आधारभूत संरचनाओं में वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है परन्तु विशेषतः उत्तर प्रदेश के परिपेक्ष में इसे सरकारी संरक्षण में नकल माफिया के हाथ सौंपकर इसकी लगभग हत्या ही कर दी गई है। आश्चर्य जनक है कि समाज, सरकार, प्रशासन और मीडिया इस न बदली जा सकने वाली सामाजिक और राष्ट्रीय बर्बादी पर चुप्पी साधे है। सारे साल स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई न के बराबर होती है। शिक्षा व्यवस्था के प्रबंध तंत्र, शिक्षक एवं छात्र सभी भाई-भतीजावाद एवं पैसों के लेन-देन से नकल कराकर प्रमाणपत्र हासिल कर लेने के दुश्चक्र में फंस चुके हैं। इस माफिया का अंग बना युवा, मेधावी बच्चों की संभावनाओं का गला काटकर अपने प्रमाण पत्र लहराकर शिक्षित दिखता है, सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है या फिर बड़े संस्थानों में प्रवेश पा लेता है, जबकि मेधावी छात्र जो इस फरेब का अंग नहीं बनना चाहते वे पीछे छूट जाते हैं। इससे उपजी अर्थव्यवस्था से सरकारी अधिकारी परीक्षा कराने वाली संस्थाएं, स्कूल-कॉलेजों के मालिक, शिक्षक, माफिया एवं निकम्मे छात्र लाभान्वित होते हैं और भारत के ताबूत में हर साल कीलें ठोक रहे हैं। आश्चर्य है कि इस सामूहिक बर्बादी पर सब चुप हैं। सरकार शायद विवश है कि वो निकम्मे और जालसाज शिक्षकों पर अच्छा काम करने का दबाव डालना नहीं चाहती, क्योंकि वह चुनाव तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रदेशों में कई बार ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्होंने बातें तो बड़ी-बड़ी की लेकिन बजाए इसके कि वो शिक्षा में सुधार लाते, उन्होंने एक ऐसा शिक्षा माफिया खड़ा कर दिया जिसने विद्यार्थियों की नकल करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया और इससे उपजने वाले धन के संग्रहण के लिए पूरी श्रृंखला खड़ी कर दी।

इलेक्शन इंजीनियर का 'बंसल मॉडल'

यूपी से लेकर बंगाल तक इस इलेक्शन इंजीनियर का स्वआविष्कृत 'बंसल मॉडल' सुपर हिट है। ये इलेक्शन इंजीनियर कोई और नहीं बल्कि भाजपा महामंत्री सुनील बंसल हैं, जिन्हें चुनाव के जमीनी और माइक्रो मैनेजमेंट में महारथ हासिल है। इनकी चुनावी रणनीति व बूथ मैनेजमेंट का अचूक नुस्खा भाजपा में पिछले 12-1× सालों में इतना कामयाब रहा है कि पार्टी व संघ दोनों ने ही इसे 'बंसल मॉडल' का नाम दे दिया है। बंगाल में भाजपा को 2 से 207 सीटों के जादुई आंकड़े तक पहुंचाने का श्रेय भी बहुत हद तक इसी चुनावी रणनीतिकार को जाता है, जो अपनी 1500 लोगों की एक समर्पित टीम के साथ 16-18 घंटे तक लगातार मैराथन चुनावी रणनीतियां बुनते हैं और इसे अमलीजामा पहनाते हैं। अपने व्यापक डेटा बैंक व इसके विश्लेषण से प्राप्त परिणामों पर अमल करते बंसल ने पहले भी यूपी के चार चुनावों में भाजपा को कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ाई हैं। 2014 से लेकर 2022 तक में संपन्न हुए लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकायों के चुनावों में भाजपा ने इसी 'बंसल मॉडल' के बलबूते खूब कामयाबी हासिल की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब भाजपा की सीटें 62 से घटकर मात्र ×2 रह गई तो इस 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की पूर्व बेला में पार्टी को फिर से 'बंसल मॉडल' की याद आई है। उन्हें 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव का जिम्मा अभी से सौंप दिया गया है, क्योंकि इस बार 'बंगाल फतेह' वाली टीम को भी सुनील बंसल ही लीड कर रहे थे। इस बार यूपी को लेकर भगवा पार्टी की चिंताएं किंचित गंभीर हैं, क्योंकि इस बार यहां जातिगत समीकरणों के अपने चटक रहे हैं, पीडीए अलग से अपनी ताकत दिखा रहा है, यूजीसी को लेकर अब भी अगड़े वर्गों में नाराजगी है, रा'य का ब्राह्मण वर्ग अपने को छला हुआ महसूस कर रहा है, प्रदेश के नेताओं की आपसी रार से भी पार्टी का अहित हो रहा है, पार्टी ने पंकज चौधरी के रूप में नया पार्टी अध्यक्ष बना तो दिया है पर इसका असर दूरगामी नहीं दिख रहा। नए अध्यक्ष चौधरी के समक्ष सबसे महती चुनौती सरकार व संगठन के बीच फिसलते समन्वय पार्टी कार्यकर्ताओं में बढ़ते असंतोष और जमीनी फीड बैक की कमी को लेकर है। भाजपा के बड़े नेताओं का मानना है कि सुनील बंसल यहां रामबाण की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि वे पार्टी के सबसे बड़े संकटमोचक भी हैं, यह काम उन्होंने बखूबी ओडिशा में भी कर दिखाया था। ये बड़े नेता लगे हाथ इन्हें पंजाब की भी जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि पंजाब में भी बंसल माइक्रोमैनेजमेंट कर बूथ लेवल तक की रिपोर्ट से उन्हें अवगत कराएं, अब देखना होगा कि यह इलेक्शन इंजीनियर एक साथ इतनी चुनौतियों को कैसे स्वीकार कर पाता है। कई रा'यों के कांग्रेस प्रमुख बदले जाएंगे - आने वाले सात रा'यों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लगाए और 2029 के आम चुनाव में भाजपा से एक निर्णायक लड़ाई लड़ने को आतुर कांग्रेस आलाकमान अपने कई प्रदेशों में अपने संगठन के चेहरे-मोहरे बदलने को आतुर है। सच पूछिए तो राहुल गांधी के दिशा-निर्देश पर यह शुरुआत कर्नाटक से हो चुकी है, जैसे ही डीके शिवकुमार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने उन्हें पार्टी अध्यक्ष की दोहरी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया और उनकी जगह एक पुराने कांग्रेसी बीके हरिप्रसाद को कर्नाटक कांग्रेस की बागडोर सौंप दी गई है। बताया जा रहा है कि अगला नंबर केरल का आने वाला है, वहां के मौजूदा अध्यक्ष सनी जोसेफ नई नवेली वीडी सतीशन सरकार में मंत्री बन गए हैं, सो उनकी जगह अपेक्षाकृत एक युवा चेहरे को लाने की बात हो रही है। राहुल गांधी चाहते हैं कि दिल्ली, पंजाब, असम, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, यूपी, झारखंड, केरल व जम्मू-कश्मीर जैसे प्रदेशों की जिम्मेदारी नए हाथों में सौंपी जाए। इसके अलावा इस बात के भी चर्चे हैं कि कम से कम चार रा'यों के प्रभारियों को भी बदला जाए। बीके हरिप्रसाद को कर्नाटक को कर्नाटक का अध्यक्ष बनाया गया है, सो हरियाणा के लिए उनकी जगह नए प्रभारी की तलाश जारी है।

महाराष्ट्र की जिम्मेदारी वहां के प्रभारी रमेश चेन्निथला के पास थी, वे भी केरल के वीडी सतीशन मंत्रिमंडल में बतौर मंत्री नियुक्त हो चुके हैं, सो उनका विकल्प भी ढूंढा जाएगा। तमिलनाडु के प्रभारी गिरीश को गोवा अध्यक्ष बनाया गया है, असम के प्रभारी जितेंद्र सिंह वहां मुंह की खाने के बाद अपने पद से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। इसी प्रकार जम्मू-कश्मीर के प्रभारी सैयद नासिर हुसैन को भी बदले जाने की चर्चा है, जबकि वे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बेहद करीबियों में शुमार होते हैं। जम्मू-कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा यूं तो राहुल गांधी के निजी पसंद बताए जाते हैं, पर उनको लेकर प्रदेश कांग्रेस में खासा बवाल मचा हुआ है, वहां के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल वानी गुट उनकी खिलाफत करता हुआ बाकायदा सड़कों पर उतर आया है, कर्रा के विरोध में उनके प्रतिद्वंद्वी गुट ने 'दिल्ली चलो' का आह्वान कर रखा है। मामले की नजाकत को भांपते हुए कांग्रेस आलाकमान ने कर्रा व उनके विरोधी गुट के नेता विकार रसूल वानी को दिल्ली तलब किया है। कांग्रेस शीर्ष चाहता है कि अगले सप्ताह इन दोनों नेताओं को आमने-सामने बिठा कर उनमें सुलह-सफाई के प्रयास किए जाएं, वैसे भी कर्रा अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे करने जा रहे हैं और कांग्रेस में आने से पहले वे महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) का हिस्सा रहे हैं, इस वजह से भी वे प्रदेश के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से ठीक से तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, शायद यह उनकी पद से रुखसती की एक बड़ी वजह हो सकती है। गांधी परिवार के नए संकटमोचक बने केजे जॉर्ज - यूं तो दिल्ली की कांग्रेसी राजनीति में केजे जॉर्ज कोई इतने जाने-पहचाने चेहरे नहीं हैं, पर इस दफे कर्नाटक में सफलतापूर्वक नेतृत्व परिवर्तन करवाने में इनकी सबसे महती भूमिका रही। दरअसल, सिद्धारमैया से डीके शिवकुमार को सत्ता हस्तांतरण ऊपर से जितना शांत लगता है दरअसल वह दुरूह सियासी झंझावातों के पेंचोखम से होकर गुजरा है। जब गांधी परिवार ने पूरी तरह मन बना लिया कि अब कर्नाटक की कमान डीके शिवकुमार के हवाले करनी है तो उन्होंने इस बाबत सिद्धारमैया को तैयार करने और उन्हें मनाने का जिम्मा 6 बार के विधायक और रा'य सरकार में मंत्री केजे जॉर्ज को सौंपा, चूंकि जॉर्ज सिद्धारमैया के भी बेहद भरोसेमंदों में शुमार होते हैं। जब 26 मई को कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धारमैया से दिल्ली आने को कहा था तो जॉर्ज भी उनके साथ दिल्ली आए थे, राहुल ने भले ही उस अहम मीटिंग से जिसमें सिद्धारमैया से वे वन-टू-वन बात कर रहे थे, अपने सभी लोगों को यहां तक कि केसी वेणुगोपाल से भी बाहर जाने को कह दिया दिया था, पर जॉर्ज सिद्धारमैया के साथ उस मीटिंग में बने रहे, जब राहुल ने यकबयक से सिद्धारमैया से अपना इस्तीफा सौंपने को कहा तो सिद्धारमैया स्तब्ध रह गए थे। फिर जॉर्ज अपने साथ सिद्धारमैया को लेकर नई दिल्ली के सुंदर नगर स्थित अपने घर पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के बीच एक बंद कमरे में घंटों बातचीत हुई। जॉर्ज ने सिद्धारमैया का गुस्सा शांत कराया और उन्हें पार्टी शीर्ष का निर्णय स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। जॉर्ज ने इसके बाद सिद्धारमैया समर्थक विधायकों से भी बात की जो जी. परमेश्वर के नेतृत्व में एक अलग गुट बनाने को हवा दे रहे थे। जॉर्ज ने सिद्धारमैया को जब उनके सम्मानजनक विदाई के लिए तैयार कर लिया तो 28 मई को सिद्धारमैया फिर से दिल्ली आए और हाईकमान को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद जार्ज सिद्धारमैया के पुत्र यतीन्द्र को अपने निजी जेट से दिल्ली लेकर आए और फिर उन्हें राहुल गांधी व खड़गे से मिलवाया। कहते हैं सिद्धारमैया की केसी वेणुगोपाल के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग जॉर्ज ने ही आयोजित करवाई थी। अब राजनैतिक पर्यवेक्षक जार्ज को गांधी परिवार का नया ऑस्कर फर्नांडिस बता रहे हैं, जो हर वक्त संकटमोचक की भूमिका के लिए मुस्तैद रहते थे। फिलहाल जार्ज रा'य के कांग्रेसी नेताओं व दिल्ली के बीच की एक अहम कड़ी बन कर उभरे हैं।

मुमकिन है आने वाले दिन में गांधी परिवार उनकी भूमिका को और 'यादा विस्तार दे, क्योंकि वे सोनिया गांधी के भी उतने ही भरोसेमंद हैं। क्या फिर से टीम बदल सकते हैं कैप्टन? - कैप्टन अमरिंदर सिंह की भगवा अहाते में छटपटाहट साफ महसूस की जा सकती है। पंजाब के इस पूर्व मुख्यमंत्री की अपने घर वापसी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। हालिया दिनों में भूपिंदर सिंह हुड्डा ने यह बयान देकर और खलबली मचा दी है कि कैप्टन कांग्रेस के संपर्क में हैं। वहीं कैप्टन की ओर से तो पंजाब भाजपा के नए चीफ केवल सिंह ढिल्लों की नियुक्ति का लगातार विरोध तो किया जा रहा है, दूसरी ओर वे यह कहना भी नहीं भूल रहे हैं कि उनका भाजपा छोड़ने का कोई इरादा नहीं। स्मरण रहे कि ढिल्लों 4 जून 2022 से पहले तक कांग्रेस में ही थे, वे कांग्रेस के टिकट पर ही 2012 में बरनाला से विधानसभा चुनाव भी जीते थे। हालांकि कुछ समय पहले कैप्टन ने यह कह कर खलबली मचा दी थी कि उनके भाई की मौत पर संवेदना व्यक्त करने के लिए उन्हें एक भी भाजपा नेता का फोन नहीं आया, वहीं राहुल गांधी ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें फोन कर संवेदना व्यक्त की थी। सूत्रों की मानें तो कोई चार-पांच महीने पहले ही कैप्टन के कांग्रेस में आने का रोड मैप तैयार हो गया था, इससे पहले कि कैप्टन अपना निर्णय सार्वजनिक कर पाते उन्हें ईडी का नोटिस आ गया और वे उसमें उलझ कर रह गए। भाजपा जानती है कि भले ही कैप्टन पार्टी में रह कर उनका कोई फायदा न करवा पाएं, पर एक बार वे फिर से कांग्रेस में चले गए तो कांग्रेस की जीत की संभावनाएं जरूर बेहतर बना सकते हैं, इसीलिए भगवा पार्टी चाहती है कि कैप्टन के ऊपर जांच एजेंसियों की तलवारें यूं ही लटकती रहें। ...और अंत में - कई हाई कोर्ट में जजों की रुकी पड़ी नियुक्तियों को सुप्रीम कोर्ट व केंद्र सरकार की हरी झंडी मिल गई है, सो, आने वाले कुछ समय में बिहार समेत कई रा'यों के हाई कोर्ट को नए जज मिल सकते हैं। पर इस बारे में हाई कोर्ट व रा'य सरकार दोनों की ही अपनी कुछ दिक्कतें हैं, जिन्होंने अपनी भावनाओं से केंद्र सरकार व सुप्रीम कोर्ट को अवगत करा दिया है। इस मामले में अब सारे कामकाज के लिए नए बेंच की व्यवस्था कब होगी, इसका इंतजार होगा।

गौ संरक्षण केंद्र से ग्रामीण स्वावलम्बन की ओर बढ़ता आगरा का गांव खेड़ा राठौर

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में कृषि और पशुपालन हमेशा से आर्थिक एवं सामाजिक जीवन की धुरी रहे हैं। बदलते समय के साथ निराश्रित और बेसहारा गोवंश की समस्या एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी थी जिसका सीधा असर किसानों की फसलों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा था। इस दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा लागू किया गया निराश्रित गोवंश संरक्षण कार्यक्रम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम साबित हुआ है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जनपदों में सुनियोजित तरीके से गोवंश आश्रय स्थलों का निर्माण और संचालन किया जा रहा है। जिला प्रशासन की कुशल देखरेख और स्थानीय जनभागीदारी के समन्वय से इन केंद्रों को न केवल पशुओं के ठहरने का स्थान बल्कि ग्रामीण विकास और पारिस्थितिक संतुलन का एक उत्कृष्ट केंद्र बनाया जा रहा है। इसी दूरदर्शी सोच का एक जीवंत उदाहरण आगरा जनपद के बाह तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम खेड़ा राठौर में देखने को मिलता है। यहाँ स्थापित वृहद गौ संरक्षण केंद्र ने पशुधन प्रबंधन और उनके कल्याण के क्षेत्र में एक नई मिसाल पेश की है। लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व स्थापित इस केंद्र ने अपनी निर्धारित परिचालन सीमाओं से आगे बढ़कर काम किया है और आज यह बेसहारा, बीमार और कमजोर गोवंश के लिए एक अत्यंत सुरक्षित और समृद्ध आश्रय स्थल का रूप ले चुका है। इस गौ संरक्षण केंद्र की सफलता का मुख्य आधार इसका मजबूत बुनियादी ढांचा और वैज्ञानिक प्रबंधन है। सामान्यतः ऐसे केंद्रों में क्षमता से अधिक पशु होने पर अव्यवस्था की स्थिति बन जाती है लेकिन यहाँ की कहानी बिल्कुल अलग है। आधिकारिक तौर पर चार सौ पशुओं की क्षमता वाले इस आश्रय स्थल में वर्तमान में चार सौ से अधिक पशु बेहद सुरक्षित परिस्थितियों में रह रहे हैं। जिला प्रशासन ने यहाँ देखभाल की गुणवत्ता से समझौता किए बिना संसाधनों का ऐसा कुशल आवंटन किया है कि हर पशु को उचित पोषण और चिकित्सा सहायता मिल रही है। यह प्रबंधन व्यवस्था जनपद के अन्य क्षेत्रों के लिए भी एक मार्गदर्शिका बन रही है। बुनियादी ढांचे की बात करें तो इस केंद्र का निर्माण लगभग एक एकड़ की विस्तृत भूमि पर किया गया है। इसकी बनावट में वैज्ञानिक और व्यावहारिक पहलुओं का पूरा ध्यान रखा गया है। उत्तर-दक्षिण दिशा में सरेखित करते हुए यहाँ एक विशाल भूसा गोदाम बनाया गया है जिसकी क्षमता चार सौ कुंतल है। उत्तर-दक्षिण दिशा के चयन के पीछे मुख्य उद्देश्य हवा की आवाजाही को बेहतर बनाए रखना और नमी को नियंत्रित करना है जिससे चारे की गुणवत्ता लंबे समय तक सुरक्षित बनी रहती है और उसमें फंगस या सड़न की समस्या नहीं होती। इसके साथ ही पशुओं को सुगमता से चारा खिलाने के लिए आधुनिक चरहियों का निर्माण किया गया है। केंद्र परिसर में चौबीस घंटे निगरानी के लिए केयरटेकर कक्ष और प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन हेतु एक समर्पित कार्यालय भी स्थापित किया गया है। इस केंद्र का स्थान चयन बहुत सावधानी से किया गया है। यह मुख्य गाँव की घनी आबादी से लगभग सौ मीटर की सुरक्षित दूरी पर स्थित है जिससे गाँव में किसी भी प्रकार की गंदगी या संक्रमण का खतरा नहीं रहता। साथ ही मुख्य मार्ग से एक पक्की सड़क द्वारा जुड़े होने के कारण यहाँ चारे की आपूर्ति, चिकित्सकीय वाहनों के आवागमन और प्रशासनिक निरीक्षण के लिए पहुँचना बेहद आसान है। इस केंद्र की सबसे बड़ी विशेषता इसकी प्राकृतिक रेतीली जमीन और उन्नत जल निकासी प्रणाली है। यहाँ पक्के ढांचे से निर्मित जल निकासी व्यवस्था दी गई है जिसमें मानसून या भारी बारिश के दिनों में भी परिसर के भीतर पानी का जमाव न हो। इसके चलते पशुओं को हर मौसम में कीचड़ मुक्त, स्वच्छ और सूखा वातावरण मिलता है जो उन्हें पैर और त्वचा की विभिन्न बीमारियों से बचाता है। संरक्षण केन्द्र में रह रहे कुल गोवंशों में बछड़े और बछड़ियों की संख्या बीस है जबकि गर्भवती और दुधारू गायों की संख्या क्रमशः आठ और सोलह है। आश्रय स्थल में वर्तमान में नर गोवंश की संख्या शून्य है। केन्द्र संरक्षण पर उन पशुओं के संरक्षण पर ज्यादा ध्यान केंद्रित है जिन्हें तत्काल सहारे और विशेष पोषण की आवश्यकता होती है। दुधारू और गर्भवती गायों के होने से केंद्र के भीतर एक सकारात्मक वातावरण निर्मित होता है। यहाँ उनके स्वास्थ्य की निगरानी के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। आगरा जनपद के संदर्भ में पशुधन संरक्षण और इसके व्यापक प्रबंधन की कार्ययोजना को बहुत ही व्यवस्थित रूप से धरातल पर उतारा गया है। जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त आंकड़ों और क्षेत्रीय सर्वेक्षण के अनुसार आगरा के इस विशेष वृहद गौ संरक्षण केंद्र में पशुओं के खान-पान, स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर दैनिक स्तर पर कड़े मानक लागू किए गए हैं। केंद्र के भीतर चार सौ से अधिक गोवंश की शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो चार सौ कुंतल क्षमता का भूसा गोदाम बनाया गया है वह मौसम की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। इसके अतिरिक्त पशुओं के लिए पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु केंद्र परिसर में प्रतिदिन लगभग दो टन हरे चारे का उत्पादन किया जा रहा है। हरा चारा पशुओं के पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने और दुधारू व गर्भवती गायों के शारीरिक पूर्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस निरंतर उत्पादन के कारण केंद्र को चारे के लिए बाहरी स्रोतों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ता जिससे वित्तीय संसाधनों की भी भारी बचत होती है। हरे चारे का यह आत्मनिर्भर मॉडल आगरा के स्थानीय स्तर पर जैविक खेती और उन्नत कृषि तकनीकों को भी बढ़ावा दे रहा है। इस पूरी व्यवस्था से केवल पशुओं को ही लाभ नहीं हुआ बल्कि गांवों को भी लाभ हो रहा है। बेसहारा गोवंश के सुरक्षित आश्रय में आ जाने से आगरा के इस क्षेत्र में किसानों की फसलों का नुकसान बंद हो गया है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। पूर्व में रात-रात भर जागकर खेतों की रखवाली करने वाले किसानों को अब इस समस्या से मुक्ति मिल गई है जिससे उनका सामाजिक और पारिवारिक जीवन सुधरा है। इसके साथ ही गोवंश के मलमूत्र से बनने वाली जैविक खाद का उपयोग खेतों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में किया जा रहा है जो रासायनिक उर्वरकों पर किसानों की निर्भरता को कम कर रही है।

स्थानीय प्रशासन, ब्लॉक स्तरीय तंत्र और ग्राम पंचायत के आपसी तालमेल ने इस केंद्र को ग्रामीण विकास और पारिस्थितिक संतुलन के एक आदर्श मॉडल में बदल दिया है। यहाँ से उत्पादित जैविक संसाधनों का पुनर्चक्रण करके पर्यावरण को संरक्षित किया जा रहा है। यह पूरी परियोजना यह स्पष्ट करती है कि किस प्रकार एक सही सरकारी पहल, जनभावनाओं और कुशल प्रशासनिक क्रियान्वयन के मेल से आगरा के ग्रामीण जीवन में व्यापक और सकारात्मक बदलाव ला सकती है। खेड़ा राठौर का यह वृहद गौ संरक्षण केंद्र आज प्रदेश के विकास मानचित्र पर एक ऐसा चमकता हुआ बिंदु बन चुका है जो पशुधन संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और ग्रामीण स्वावलंबन की सामूहिक शक्ति को पूरी प्रामाणिकता के साथ प्रदर्शित करता है। उत्तर प्रदेश सरकार की इन योजनाओं की व्यापकता केवल एक जनपद या एक केंद्र तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे राज्य में पशुधन के विकास और संरक्षण की नई गाथा लिखी जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में की गई समीक्षा के अनुसार राज्य में वर्तमान में कुल सात हजार पांच सौ सत्ताइस गो-आश्रय स्थल संचालित हैं जिनमें बारह लाख उनतीस हजार से अधिक गोवंश पूरी तरह संरक्षित हैं। इस विशाल व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्हें अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसके अंतर्गत छह हजार चार सौ तैंतीस अस्थायी स्थलों में नौ लाख निवासी हजार गोवंश, पांच सौ अठारह वृहद गो-संरक्षण केन्द्रों में एक लाख अट्ठावन हजार गोवंश, तीन सौ तेईस कान्हा गो-आश्रयों में सत्तहत्तर हजार नौ सौ पचीस गोवंश तथा दो सौ त्रेपन कांजी हाउस में तेरह हजार पांच सौ छिहत्तर गोवंश को आश्रय दिया गया है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने बदन ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पेरिफेरल एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/[illegible])

नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्र का जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा

कुशीनगर।

नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा के प्रथम दिवस जिलाधिकारी ने परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जनपद में यह परीक्षा 8 जून से 10 जून 2026 तक पांच केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

इसी क्रम में जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ किसान इंटर कॉलेज, साखोपार स्थित परीक्षा केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परीक्षा केंद्र के कंट्रोल रूम का अवलोकन करते हुए सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, कवरेज क्षेत्र तथा निगरानी व्यवस्था की गहन समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्र की प्रत्येक गतिविधि पर सतत निगरानी रखी जाए ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना न रहे। जिलाधिकारी ने ड्यूटी पर

तैनात पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पूरी सतर्कता, जिम्मेदारी और निष्पक्षता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए।

उन्होंने परीक्षा केंद्र व्यवस्थापकों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर शासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा की शुचिता एवं निष्पक्षता सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर इससे समझौता नहीं किया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल एवं निगरानी व्यवस्था तैनात की गई है। परीक्षा प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करने, अफवाह फैलाने अथवा कानून-व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि अभ्यर्थियों को निष्पक्ष, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित परीक्षा वातावरण उपलब्ध कराने के लिए जनपद प्रशासन एवं पुलिस विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।

बेटे की हरकतों से त्रस्त पिता ने पुलिस से मांगी मदद

कुशीनगर। स्थानीय थाना क्षेत्र के पिपरा बुजुर्ग गांव निवासी एक व्यक्ति ने अपने पुत्र के कथित अनुचित व्यवहार से परेशान होकर जिलाधिकारीझपुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित पिता अयोध्या गुप्ता का आरोप है कि उनका लगभग 19 वर्षीय पुत्र सागर गलत संगति में पड़कर भटक गया है और आए दिन अनुचित गतिविधियों में शामिल रहता है। उसके व्यवहार के कारण गांव और समाज के लोग लगातार शिकायत लेकर घर पहुंचते हैं, जिससे परिवार को सामाजिक अपमान और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है।पिता ने बताया कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने कई बार पुत्र को समझाने और सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया, लेकिन वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। विरोध करने पर वह परिवार के सदस्यों को धमकी भी देता है। इससे पूरा परिवार भय और

तनाव के माहौल में जीवन यापन कर रहा है। प्रार्थना पत्र में पिता ने पुत्र को अपनी चल-अचल संपत्ति से बेदखल करने की बात भी कही है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि भविष्य में पुत्र द्वारा किए जाने वाले किसी भी गलत कार्य, विवाद या आपराधिक घटना के लिए परिवार जिम्मेदार नहीं होगा। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से मामले को अभिलेख में दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।

खड्डा विधायक को पत्रकारों ने सौंपा पत्रक, सुरक्षा कानून लागू करने और प्रेस क्लब की मांग

खड्डा,कुशीनगर।

अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति (एबीपीसएस) तहसील इकाई खड्डा, कुशीनगर द्वारा विधायक खड्डा विवेकानंद पांडेय को पत्रक सौंपकर खड्डा में प्रेस क्लब की स्थापना करने और पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग की। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिग्नेश कलवाड़ियां और प्रदेश अध्यक्ष अजय प्रताप नारायण सिंह के निर्देशन में जिलाध्यक्ष हृदया नन्द शर्मा, जिला सचिव मसरूर रिजवी, तहसील अध्यक्ष खड्डा उग्रसेन कुमार गुप्ता के नेतृत्व में सोमवार को विधायक आवास पर पत्रक सौंपकर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकारों ने खड्डा उपनगर में एक प्रेस क्लब हेतु भूमि की उपलब्धता और उस पर भवन की स्थापना और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की। पत्रकारों ने विधायक श्री पांडेय का अभिनंदन हुए कहा कि खड्डा में

पत्रकारों को अपनी खबरों के संकलन, आदान प्रदान, संपादन को लेकर कोई सुविधा नहीं होने से काफी दिक्कत होती है ऐसे में खड्डा नगर में प्रेस क्लब हेतु भूमि की उपलब्धता और उस पर भवन की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। जहां पत्रकार एक स्थान पर बैठकर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, विकास, शिक्षा, विज्ञान, खेलकूद एवं जनहित से जुड़ी खबरों का संकलन, संपादन एवं आदान-प्रदान कर सकेंगे तथा समाज में सकारात्मक एवं जागरूक वातावरण के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। साथ ही मांग किया कि पत्रकारों को अपने कार्य के दौरान विभिन्न प्रकार की चुनौतियों एवं कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कई बार समाचार संकलन के दौरान उनकी सुरक्षा भी प्रभावित होती है। ऐसे में इस मुद्दे को विधानसभा में प्रमुखता से उठाया जाय। विधायक श्री पांडेय ने आश्वस्त किया कि खड्डा में बहुत जल्द प्रेस क्लब की स्थापना की जाएगी। कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। सरकार पत्रकारों के

पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ- विधायक विवेकानंद पांडेय प्रेस क्लब की स्थापना और मुख्यमंत्री को पत्र लिखने का विधायक खड्डा ने दिया आश्वासन

मान, सम्मान और हक के लिए सदैव तत्पर है। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगा और उनसे वार्ता कर सार्थक कदम उठाया जायेगा। इस दौरान जिला कार्य समिति सदस्य संदीप कुमार सिंह, कन्हैया मणि त्रिपाठी, पन्नालाल यदुवंशी, मो हिदायत, अभय राय, राहुल गुप्ता, केशव गुप्ता, साबिर, शैलेश यदुवंशी, आनंद सिंह, दिवाकर कुमार, मो मुबारक, मो अल्ताफ हुसैन सहित भारी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे।

कल्याणकारी शिविर मे सदर विधायक ने लाभार्थियों को बांटे प्रमाण-पत्र व उपकरण

सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी बोले– अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंचे सरकारी योजनाएं

देवरिया।

शासन की मंशा के अनुरूप अंतिम पायदान पर खड़े पात्र व्यक्तियों को सीधे लाभान्वित करने के उद्देश्य से सोमवार को सदर तहसील सभागार में एक वृहद कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी के दिशा-निर्देशन में आयोजित इस शिविर में जिला समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने संयुक्त रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान की मूल भावना पर आधारित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी शामिल हुए, जिन्होंने विभिन्न योजनाओं के चयनित लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र और सहायक उपकरण वितरित किए। शिविर के दौरान विभागीय अधिकारियों ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया, जिसके बाद क्रमवार वितरण प्रक्रिया शुरू हुई। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से 10 दिव्यांग जनों को कान की मशीन, ट्राइसाइकिल, छड़ी और विधिक प्रमाण-पत्र सौंपे गए। इसी प्रकार, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित ओ-लेवल कंप्यूटर कोर्स के 30 सफल छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र दिए गए। समाज कल्याण विभाग की ओर से 10 वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन की स्वीकृति और महिला कल्याण विभाग की ओर से कन्या सुमंगला व निराश्रित महिला पेंशन की 10 लाभार्थियों को विधिक प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 15 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के स्वीकृति पत्र मुख्य अतिथि के कर-कमलों द्वारा प्रदान किए गए। समारोह को संबोधित करते हुए सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ समाज के गरीब, पिछड़े और बेसहारा वर्ग को संबल प्रदान कर रही है। उन्होंने विकास कार्यों और अपनी प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वे शासकीय योजनाओं को केवल फाइलों तक सीमित न रखकर गाँव-गाँव और घर-घर तक पहुँचाएं, ताकि कोई भी वास्तविक पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। इस अवसर पर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी प्रियंका चौधरी, मुख्य वक्फ निरीक्षक मनोज कुमार राय सहित संबंधित कल्याण सेक्टर्स के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

टूटते परिवार बचे- मध्यस्थता केंद्र में सुलझा दो दंपतियों का विवाद, साथ रहने को हुए राजी

देवरिया।

बिखरते रिश्तों को सहेजने और पारिवारिक ताने-बाने को अक्षुण्ण बनाए रखने की दिशा में जिला मुख्यालय पर एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक सफलता मिली है। दीवानी न्यायालय परिसर स्थित मध्यस्थता एवं सुलह समझौता केंद्र (एडीआर भवन) में सोमवार को दो गंभीर पारिवारिक वादों का आपसी सहमति से सुखद निस्तारण कराया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अर्चना के कुशल नेतृत्व और मध्यस्थों के सहयोग से दोनों पीड़ित दंपतियों ने अपनी पुरानी कड़वाहट और मतभेदों को भुलाकर पुनः एक साथ सम्मानपूर्वक जीवन बिताने का निर्णय लिया। प्राप्त विवरण के अनुसार, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एफटीसी न्यायालय द्वारा विधिक मध्यस्थता हेतु संदर्भित किए जाने पर दो अलग-अलग मामले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्राप्त हुए थे। इसमें पहला मामला मुकदमा संख्या 6367/2024 (रेनू बनाम राम पुकार पाल) तथा दूसरा मामला मुकदमा संख्या 5750/2026 (बबली बनाम रामू यादव) का था। सोमवार को प्राधिकरण की सचिव अर्चना के समक्ष दोनों मामलों के पक्षकार उपस्थित हुए। इसके बाद अधिकृत

सिविल जज एवं विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अर्चना की पहल पर दो वैवाहिक मामलों का हुआ सुखद निस्तारण सचिव बोलीं– आपसी सहमति से विवाद सुलझाना ही मुख्य उद्देश्य, यहां दोनों पक्षों की होती है जीत

मध्यस्थ प्रेमनाथ और रीता पांडेय के सहयोग से दोनों पक्षों के बीच मैराथन काउंसिलिंग कराई गई और उन्हें पारिवारिक जीवन के महत्व का बोध कराया गया। सकारात्मक विधिक संवाद और आपसी काउंसलिंग के फलस्वरूप दोनों जोड़े एक-दूसरे के साथ पति-पत्नी के रूप में रहने को सहर्ष तैयार हो गए, जिस पर न्यायालय परिसर में ही दोनों पक्षों का सफल निस्तारण कराया गया। इस अवसर पर सचिव अर्चना ने कहा कि मध्यस्थता का मुख्य ध्येय मुकदमों को लंबा खींचने के बजाय विवादों को आपसी रजामंदी से हल करना है। यह प्रक्रिया आपसी संबंधों को टूटने से बचाती है और पक्षकारों को स्वयं अपना मामला सुलझाने का विधिक अधिकार देती है। इसमें कोई भी पक्ष हारता नहीं, बल्कि दोनों पक्षों की जीत होती है। उन्होंने आमजन और अधिवक्ताओं से अपील की कि वे अपने वादों को न्यायालय के माध्यम से मध्यस्थता केंद्र में संदर्भित कराएं। इसके साथ ही उन्होंने स्थायी लोक अदालत का प्रचार-प्रसार करते हुए बताया कि जनोपयोगी सेवाओं जैसे– विद्युत, सड़क, वायु व जलमार्ग परिवहन, डाक, तार, टेलीफोन, स्वच्छता, जलापूर्ति, चिकित्सालय तथा बीमा सेवाओं से जुड़े विवादों को भी स्थायी लोक अदालत के माध्यम से त्वरित और प्रभावी ढंग से निस्तारित कराया जा सकता है।

रिटायर हो चुके अग्निवीरों के लिए एलजी का स्पेशल प्लान, अब दिल्ली फायर ब्रिगेड में निभाएंगे अहम भूमिका

नई दिल्ली। दिल्ली में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने और फायर विभाग में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए पूर्व अग्निवीरों को नियुक्त करने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह ने सुझाव दिया कि फायर विभाग में रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए पूर्व अग्निवीरों की सेवाएं ली जाएं। उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह मंत्री आशीष सूद और मंत्री प्रवेश वर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में राजधानी में फायर सेफ्टी, अवैध निर्माण, हीट वेव एक्शन प्लान और मानसून की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान यह बात सामने आई कि दिल्ली फायर सर्विस को अधिक प्रभावी और त्वरित प्रतिक्रिया देने वाली एजेंसी बनाने के लिए मानव संसाधन बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में एलजी ने कहा कि सेना में प्रशिक्षित होकर लौटने वाले पूर्व अग्निवीर अनुशासन, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने का अनुभव रखते हैं, जिसका लाभ फायर विभाग को मिल सकता है। इसके साथ ही राजधानी में फायर स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की योजना पर भी चर्चा हुई, ताकि किसी भी आगजनी या आपदा की स्थिति में प्रतिक्रिया समय कम किया जा सके। अधिकारियों का मानना है कि पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति से न केवल रिक्त पदों को भरने में मदद मिलेगी, बल्कि फायर सर्विस की कार्यक्षमता और आपदा प्रतिक्रिया क्षमता भी मजबूत होगी। बैठक में फायर सुरक्षा नियमों के सख्त पालन, बहुमंजिला इमारतों में अग्नि सुरक्षा उपायों के विस्तार और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया गया। हालांकि, पूर्व अग्निवीरों को फायर विभाग में शामिल करने का सुझाव बैठक का सबसे प्रमुख निर्णय माना जा रहा है, क्योंकि इससे अग्निवीर योजना से लौटे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुल सकते हैं। एलजी ने शहर में जारी अवैध निर्माण और फायर सेफ्टी लाइसेंस के दुरुपयोग के मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि खुलेआम हो रहे गैरकानूनी निर्माण और अनधिकृत प्लॉटिंग पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। एलजी ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है और यहां प्रशासनिक शक्तियों के कम उपयोग या बहानों के लिए कोई जगह नहीं है। एलजी ने चेतावनी दी कि किसी भी अधिकारी की लापरवाही, उदासीनता या कार्य निष्पादन में कमी का सीधा प्रभाव उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) की ग्रेडिंग पर पड़ेगा।

दिल्ली फायर सर्विस एक्ट की धारा 32 होगी सख्ती से लागू

बैठक में गृह मंत्री आशीष सूद के उस सुझाव को भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत दिल्ली फायर सर्विस एक्ट-2007 की धारा 32 को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके तहत राजधानी की सभी बहुमंजिला इमारतों में अग्नि सुरक्षा उपाय लागू होंगे, चाहे उन्हें फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की आवश्यकता हो या नहीं।

होर्मुज में जलते जहाज से 24 भारतीयों का रेस्क्यू

ईरान बोला- अब इजराइल पर हमले नहीं; भारत ने नागरिकों को ईरान छोड़ने को कहा

तेल अवीव। होर्मुज स्ट्रेट के पास एक तेल टैंकर में आग लगने के बाद उस पर सवार 24 भारतीय नाविकों को इंडियन नेवी ने बचा लिया है। शुरुआती रिपोर्टों में जहाज पर हमले की आशंका जताई गई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच ईरान ने घोषणा की है कि उसने फिलहाल इजराइल के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई रोक दी है। हालांकि उसने चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने फिर से लेबनान या अन्य जगहों पर हमला किया तो उसे पहले से ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका युद्धविराम और शांति समझौते की कोशिशों में जुटा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने दावा किया है कि इजराइल और ईरान दोनों संघर्ष रोकना चाहते हैं और अंतिम समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि समझौता होने तक ईरान पर लगी नाकाबंदी जारी रहेगी। हालात को देखते हुए भारत सरकार ने ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द वहां से निकलने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर भारतीयों की मदद के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

पिघले हुए लोहे की चपेट में आने से आठ श्रमिकों की मौत; पीएम ने जताया दुख

विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में हुए एक बड़े हादसे में आठ श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना एसएमएस-2 और एसटीसी-3 हीट फैसिलिटी में बड़ी मात्रा में पिघले हुए स्टील के रिसाव के कारण हुई। हादसा उस समय हुआ जब क्रेन के जरिये ले जाए जा रहे पिघले लोहे से भरी बाल्टी से गर्म धातु नीचे गिर गई। अधिकारियों के अनुसार, अब तक पांच शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि राहत एवं बचाव कार्य जारी है। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए पीड़ितों की मदद का एलान किया है। विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में पिघला हुआ लोहा गिरने से कम से कम आठ मजदूरों की मौत हो गई।

इस हादसे में छह अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल मजदूरों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। पीएम मोदी ने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद देने का एलान किया है। विशाखापत्तनम जिला स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव को बताया कि सोमवार शाम 6.30 बजे तक आठ मृतकों में से छह के शव इस्पात संयंत्र के सामान्य अस्पताल पहुंच चुके हैं। पुलिस ने बताया कि हादसे के समय पिघले लोहे का तापमान करीब 1,600 डिग्री सेल्सियस था। अत्यधिक गर्म धातु मजदूरों पर गिरने से वे इसकी चपेट में आ गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख जताया और सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ राहत कार्य तथा प्रभावितों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी विभाग समन्वय से काम करें और सहायता प्रदान करें। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस घटना में साइट पर मौजूद कई कर्मचारी बुरी तरह झुलस गए हैं। रिसाव के बाद आग लगने से कुछ कर्मचारियों के यूनिट के अंदर फंसे होने की आशंका है। फायर और इमरजेंसी सर्विस की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने व बचाव कार्य में जुटी हैं। घायल और फंसे हुए कर्मचारियों की सही संख्या की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

फिलीपींस में 7.8 तीव्रता का भूकंप, इमारतें गिरीं- 32 लोगो की मौत

मनीला। फिलीपींस में सोमवार सुबह 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। प्रभावित इमारतों में ज्यादातर दुकानें, दफ्तर और व्यावसायिक भवन शामिल हैं। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक अब तक 32 लोगों की मौत हुई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक, भूकंप भारतीय समयानुसार सुबह 5:07 बजे आया। भूकंप का केंद्र मिंडनाओ द्वीप के पास समुद्र में था। यह सारंगानी प्रांत के मासीम कस्बे से लगभग 32 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में और 33 किलोमीटर की गहराई पर आया। अधिकारियों का कहना है कि यह इस साल फिलीपींस में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है।

इंडिया गठबंधन की बैठक पर संबित पात्रा का तंज- अब स्टेडियम नहीं, एक कमरे का ड्रामा!

नई दिल्ली। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की दो साल बाद हुई बैठक को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर तंज कसा है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि ये इनकी बैठक नहीं, बल्कि इंडी गठबंधन वालों का एक ड्रामा चल रहा है। ये हर तीसरे महिने एक चुनाव हारेंगे और हर दूसरे महिने में इनकी बैठक होगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव हारने का शतक लगाया है। लेकिन आज ऐसे हंस रहे थे जैसे बहुत बड़ा दुर्ग फतह करके आए हैं। पात्रा ने कहा कि आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में इंडी गठबंधन वालों की बैठक हुई। इसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एसआईआर हुआ, वोट चोरी हुई। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि ये एक ही टेप रिकॉर्डर कब से चला रहे हैं। एसआईआर तो तमिलनाडु में भी हुआ, केरल में भी हुआ, लेकिन

सरकार बना ली। लेकिन जब बंगाल में हार गए तो एसआईआर को कोस रहे हैं, एसआईआर का रोना रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पाखंड की पराकाष्ठा को हम सब और हिंदुस्तान की जनता देख रही है। अगर सही मायने में कुछ चोरी हुआ है तो इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। आज जमीन में इनमें से किसी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सर्वदलीय बैठक की मांग करते हैं। लेकिन पिछली बार जब नारी सशक्तिकरण के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी, सब नदारत थे। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहे हैं। जनता ने इन्हें पूरी तरह से इन-एक्टिव कर दिया है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि पहले ये सभाएं स्टेडियमों में होती थीं, और बेंगलुरु स्टेडियम में सभी लोग हाथ पकड़कर खड़े होते थे। धीरे-धीरे ये बैठकें कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एक कमरे में सिमट गई है; अब स्टेडियम नहीं भरते...तमिलनाडु में आप (कांग्रेस) तुरंत वहाँ पहुँचे, दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन किया और सरकार बना ली...बंगाल में हारने के बाद अब वे धांधली का आरोप लगा रहे हैं। पूरा देश इस घोर पाखंड का गवाह है...इनमें से किसी भी राजनीतिक दल की जमीनी स्तर पर कोई वास्तविक उपस्थिति नहीं है। उनकी ईमानदारी खत्म हो गई है, और इसी ईमानदारी के खत्म होने के कारण जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया। संबित पात्रा ने कहा कि अखिलेश यादव भी आ चुके थे, और ममता जी को देखकर उन्हें भी यही लग रहा होगा कि कुछ ही देर में मेरा भी यही हाल होगा। जहां राहुल मौजूद होते हैं, वहां किसी का भाग्य नहीं चमकता... उनकी (इंडी गठबंधन की) बैठक हर दो महीने में होनी तय है। इसलिए, मुझे लगता है कि तीसरी या चौथी बैठक तक तो कार के अंदर ही बैठक होगी।

20 सांसदों के साथ एनडीए को समर्थन देने के लिए ओम बिरला को भेजा पत्र

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर घिरा राजनीतिक संकट अब और गहराता जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद 58 विधायकों की बगावत से जूझ रही टीएमसी को अब संसद में भी बड़ा झटका लगा है। तृणमूल कांग्रेस में टूट की अटकलों पर सोमवार को पार्टी की लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने मुहर लगा दी है। सांसद काकोली घोष ने कहा है कि मेरे साथ टीएमसी के करीब 20 सांसदों ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई से काकोली घोष ने कहा कि 20 टीएमसी सांसदों के हस्ताक्षर वाला पत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजकर एनडीए के साथ गठबंधन करने की इच्छा जताई गई है। वरिष्ठ पार्टी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया कि लगभग 20 टीएमसी सांसदों ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के समर्थन के लिए लोकसभा अध्यक्ष को अपनी स्थिति से अवगत करा दिया है। टीएमसी के वर्तमान में 28 लोकसभा सांसद और 12 राज्यसभा सांसद हैं। यह दावा करते हुए कि वह लोकसभा में पार्टी की मुख्य सचेतक बनी हुई हैं, दस्तीदार ने कहा कि

यह फैसला साथी सांसदों के साथ विचार-विमर्श के बाद लिया गया है। यह घटनाक्रम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी के भीतर बढ़ते आंतरिक संकट के बीच आया है, जिसने हाल के दिनों में वरिष्ठ नेताओं के खुले विरोध और इस्तीफों को देखा है। घोष दस्तीदार ने कहा कि समूह ने राजनीतिक रूप से एनडीए के साथ खुद को जोड़ने का फैसला किया है, यह तर्क देते हुए कि यह जनमत को दर्शाता है। उन्होंने कहा, हमने जनता के फैसले को स्वीकार कर लिया है और मानते हैं कि हमारे भविष्य के राजनीतिक मार्ग को एनडीए के हिसाब से होना चाहिए। टीएमसी नेतृत्व ने अभी तक इन दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

नितिन गडकरी की बड़ी घोषणा- सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को बचाने वाले रहवीरों को मिलेगा 25,000 का इनाम

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 8 जून को भारत में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के उद्देश्य से दो नई पहलों की घोषणा की, जिनमें आपातकालीन स्थिति में सबसे पहले पहुंचने वाले नागरिकों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी शामिल है। इन उपायों के बारे में बताते हुए गडकरी ने कहा कि हमने दो योजनाएं शुरू की है। एम्स के एक डॉक्टर की अध्यक्षता वाली एक समिति ने रिपोर्ट दी है कि हमारे देश में प्रतिवर्ष 180,000 मौतें और 500,000 दुर्घटनाएं होती है। इन दुर्घटना पीड़ितों में से 30% को अगर तुरंत अस्पताल ले जाया जाए, तो बचाया जा सकता है, यानी 50,000 जानें। त्वरित जन सहायता को प्रोत्साहित करने के लिए, मंत्रालय ने रहवीर पहल शुरू की। गडकरी ने बताया कि यदि लोग इन 50,000 लोगों को अस्पताल पहुंचाने में मदद करते है, तो उनकी जान बचाई जा सकती है; हम ऐसे जीवनरक्षकों को 'रहवीर' कहते है, और बचावकर्ता को 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सरकार आपातकालीन चिकित्सा देखभाल में आने वाली वित्तीय बाधाओं को दूर

करेगी। मंत्री ने आगे कहा कि इसके बाद, सड़क के प्रकार की परवाह किए बिना - चाहे वह राष्ट्रीय, जिला या नगरपालिका हो - और जिस भी अस्पताल में पीड़ित को भर्ती कराया जाता है, हम सात दिनों तक के उपचार खर्च को तुरंत वहन करेंगे, अस्पताल के बिल का भुगतान अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक करेंगे। स्थिति की गंभीरता पर जोर देते हुए गडकरी ने कहा, मेरा मानना है कि ये योजनाएं एक महत्वपूर्ण मुद्दे का समाधान करती है, क्योंकि हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या विश्व स्तर पर सबसे अधिक है। यदि सभी सहयोग करें, तो हम अनगिनत जानें बचा सकते हैं। उन्होंने निजी क्षेत्र की भागीदारी का भी उल्लेख करते हुए कहा कि आज रैपिडो ने पहल की है और अपना समर्थन देने का वादा किया है। अलग से, रेल मंत्रालय ने 6 जून को लुधियाना में नई दिल्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्पेशल ट्रेन के एक स्लीपर कोच में दरार पाए जाने के बाद देशव्यापी सुरक्षा अभियान शुरू किया और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) के सभी कोचों के व्यापक निरीक्षण के आदेश दिए। रेल मंत्रालय ने सभी जोन को निर्देश दिया है कि वे जंग, क्षरण और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संरचनात्मक कमजोरियों पर विशेष ध्यान देते हुए विस्तृत जांच करें। यह जांच एक सप्ताह के भीतर पूरी होने की उम्मीद है। अत्यधिक जंग या संरचनात्मक खराबी वाले डिब्बों को यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेवा से हटा दिया जाएगा।

इंडिया गठबंधन की बैठक में बोले राहुल गांधी- एक साल में गिर जाएगी मोदी सरकार

नई दिल्ली। इंडिया गठबंधन की उच्च स्तरीय बैठक से एक बड़ी खबर सामने आई है। सामने आई जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार के भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि देश की जनता के भीतर मौजूदा सरकार के प्रति भारी असंतोष है और अगर यही ढर्रा जारी रहा, तो अगले एक साल के भीतर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। गठबंधन की इस अहम बैठक में राहुल गांधी ने सरकार की अंतरराष्ट्रीय रणनीतियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मिडिल ईस्ट में जारी तनावपूर्ण हालातों पर भारत सरकार का रुख बेहद अस्पष्ट और ढुलमुल रहा है। राहुल गांधी ने केंद्र पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका के साथ की गई डील के नाम पर सरकार ने देश के अन्नदाताओं (किसानों) के हितों की अनदेखी की है। इस दौरान राहुल गांधी ने पेपर लीक और बेरोजगारी को लेकर कहा कि देश के नौजवानों के भविष्य के साथ सरेआम खिलवाड़ हो रहा है। लगातार हो रहे पेपर लीक सरकारी तंत्र की घोर लापरवाही का नतीजा है। आज देश का युवा बेरोजगारी और महंगाई की दोहरी मार झेल रहा है, जिससे जनता के बीच भारी आक्रोश है।

इंडिया गठबंधन ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा

नई दिल्ली। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने सोमवार को एकजुटता प्रदर्शित करते हुए सोमवार को लाखों युवाओं के भविष्य के साथ विश्वासघात करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और कहा कि वह वोट लूट को लेकर जल्द ही प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत को पत्र लिखेगा। गठबंधन ने यहां कांस्टीट्यूशन क्लब में करीब ढाई घंटे की बैठक के बाद केंद्र सरकार सरकार से गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, किसानों तथा जनसरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की बुलाने की मांग भी की। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) के घटक दलों के नेताओं ने यह सहमति भी जताई कि वे हर दो महीने पर बैठक करेंगे और उनकी अगली बैठक आगामी अगस्त महीने में हैदराबाद में होगी। इस बैठक में चिकित्सा पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली से जुड़े विवाद, देश की आर्थिक स्थिति के साथ ही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विषय पर चर्चा की गई। बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के तेजस्वी यादव और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शप) की सुप्रिया सुले समेत 22 दलों के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख एवं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता एवं जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की नेता महबूबा मुफ्ती, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के जॉन ब्रिटास, भाकपा महासचिव डी. राजा, भाकपा (माले) लिबरेशन के दीपांकर भट्टाचार्य, निर्दलीय राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल और कई अन्य दलों के नेताओं ने भाग लिया। बैठक के बाद खरगे ने संवाददाताओं से कहा कि इंडिया गठबंधन ने पांच बिंदुओं पर सहमति जताई है और इसके

वोट लूट पर सीजेआई को लिखेगा पत्र

घटक दल इन सभी बिंदुओं पर डटकर काम करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। खरगे ने बताया, यह सहमति बनी कि वोट लूट, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनावों की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय प्रधान न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। यह पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए, सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग की जाए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवाओं के साथ विश्वासघात हुआ है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, किसानों तथा जनसरोकार से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार को तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। खरगे ने कहा, (संसद के) मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रतिदिन प्रातःकाल माननीय नेता प्रतिपक्ष (मल्लिकार्जुन खरगे) के कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) और आम आदमी पार्टी (आप) बैठक में शामिल नहीं हुईं। आप पहले ही सार्वजनिक रूप से इस गठबंधन से दूरी बना चुकी है जबकि द्रमुक ने तमिलनाडु में कांग्रेस द्वारा उससे संबंध तोड़कर टीवीके-नीत सरकार में शामिल होने के बाद बैठक का बहिष्कार करने का फैसला करने की घोषणा की थी बैठक में तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के शामिल नहीं होने से जुड़े सवाल पर कांग्रेस सूत्रों ने कहा, टीवीके इस बैठक में शामिल नहीं हुई क्योंकि केवल उन पार्टियों को आमंत्रित किया गया था, जिनके संसद में सदस्य हैं। सूत्रों ने कहा, 2024 से पहले इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाली कुछ पार्टियां आज की बैठक में शामिल रहीं, भले ही उनके पास वर्तमान में सांसद नहीं हैं। इंडिया गठबंधन विस्तार की राह पर है, जल्द ही और पार्टियां इसमें शामिल होंगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हालिया हार ने भी विपक्षी गठबंधन को देश में भाजपा के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एकजुट होने को मजबूर किया। इससे पहले, इंडिया गठबंधन की आधिकारिक बैठक जून, 2024 में हुई थी। बैठक में दिए शुरुआती संबोधन में खरगे ने सोमवार को इंडिया गठबंधन के दलों का आह्वान किया कि वे मोदी सरकार द्वारा खड़ी की गई चुनौतियों से निपटने के लिए उस एकजुटता की भावना को और मजबूत करें, जो इस साल 17 अप्रैल को महिला आरक्षण एवं परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के खिलाफ दिखी थी। उन्होंने यह दावा भी किया कि सरकार संविधान पर हमला जारी रखे हुए है।